







# भारतीय वोटर तथ करेंगे ट्रम्प का भविष्य

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस वक्त भारत पर कुछ ज्यादा ही मेहबूबान हैं इसकी वजह आगामी चुनाव में खुद को एक बार पिछे अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में देखना हैं भारत और चीन के एलएसी के मुद्दे ही ट्रम्प का हर बयान भारत के पथ में दिखता है दिखना भी चाहिए वजह है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस इस ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया, चीन से उत्पन्न हुए इस वायरस ने लाखों अमेरिकन की जान ले ली अमेरिका कहीं न कहीं मानता हैं इसमें चीन की साजिश है, पर खुल कर कुछ कह नहीं पाता अब अमेरिका के राष्ट्रपति युनाव में कुछ ही समय शेष बचा है ट्रम्प अपनी पूरी ताकत भारतविरियों पर लगाए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार पिछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं और एक महान नेता हैं, अमेरिका के साष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाए मात्रा को लेकर कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं और वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ भी आसान नहीं है लेकिन वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत को एक महान नेता मिला है और एक महान व्यक्ति मिला है। इस साल प्लायवरी में प्लॉट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ भारत की अपनी दो दिवसीय यात्रा के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमारे पास एक अविश्वसनीय समय था और हमने देखा कि लोग कितने अविश्वसनीय हैं। यह एक अविश्वसनीय जगह और देश है और यह निश्चित रूप से बड़ा है, साथ ही हूस्टन में हाउटी मोदी कार्यक्रम के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक शानदार झंगेट था, यह अविश्वसनीय था। प्रधानमंत्री मोदी अधिक उदार नहीं हो सकते थे। हमें भारत और पीएम मोदी से बहुत समर्थन है, मुझे लगता है कि भारतीय-अमेरिकी ट्रंप के लिए जातदान करेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आगामी नवंबर में

हन वाल राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर भारतीय मूल के अमेरिकी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारत दौरे से लौटने के तुरंत बाद ट्रम्प ने उन्हें प्रभावित करने के लिए योजना बनाई। अमेरिका में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति के चुनावी कैपेन में भारतवर्षी समुदाय के लिए एड कैपेन आ रहा है। इसकी वजह यह है कि युनान में 14 लाख भारतीय मूल के अमेरिकी निर्णायक हो सकते हैं। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि 2016 में हुए पिछले चुनाव में 84: भारतीय अमेरिकियों ने ट्रम्प के खिलाफ वोट दिया था। राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रम्प लगातार भारतवर्षीयों में पैठ बना रहे हैं। वे प्रशासन में 22 भारतवर्षीयों को शामिल कर चुके हैं। यह किसी भी प्रगासी समूह का अब तक का सबसे बड़ा टल है। इनमें निककी हेली यूएन में अमेरिकी राजदूत, सीमा वर्मा को मेडीकेयर और मेडीफेड सर्विस का प्रशासक बनाया। राज शाह को लाइट हाउस

क कम्युनिकेशन डायरेक्टर ह, वहाँ अजीत पाई फेदल कम्युनिकेशन कमीशन के घेयरमैन हैं। 14 लाख रजिस्टर्ड वोटर, सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत। एशियन अमेरिकन और पैसिपिक आइलैंडर्स डेटा के मुताबिक 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में 12 लाख भारतवंशी रजिस्टर्ड वोटर थे। इस बार 14 लाख होने की उम्मीद है। पिछली बार प्रवासियों में सबसे ज्यादा 62% वोटिंग भारतवंशियों की रही है। 2016 के चुनाव में 84% भारतीयों ने ट्रम्प का विरोध किया था। 62% भारतवंशी खुद को डेमोक्रेटिक बताते हैं। 2016 के चुनाव में 80% से ज्यादा भारतीयों ने ट्रम्प की प्रतिवंशी उम्मीदवार लिलेटी विलंटन को वोट दिया था। पिछला अमेरिका में 5 भारतीय अमेरिकी सांसद हैं। ये सभी डेमोक्रेटिक हैं। इनमें से एक्सा (कैलिफोर्निया), प्रामिला जयपाल (वॉशिंगटन), राजा कृष्णमूर्ति (इलिनोइस), तुलसी गैबर्ड (हवाई) और कमला हैरिस (कैलिफोर्निया) शामिल हैं। ट्रम्प पहले विजापन में गेलानिया के साथ ताज महल के

पाकिस्तान ने लिए कदम 2001 में दिसंबर में उत्तरी अमेरिका बायोडिवर्सिटी और सामाजिक विवरणों के साथ दिखाया था। इनका दूसरे विज्ञापन में द्रग्म मोटी के साथ है। अमेरिका को भारत को प्यार करता है। अमेरिका भारत के साथ मजबूत साझेदारी की छाँचा देखता है। भारत में बने नीम्स और इवांका ने संजीदा जवाब दिए हैं। ऐसेंगर दिलजीत दोसांझा ने इवांका के ताजमहल विजिट की तस्वीर में खुद को इवांका के साथ दिखाया था। इवांका ने लिखा- शुक्रिया, मुझे आनंदाद ताजमहल दिखाने के लिए। यह अनुभव मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दूसरे नीम पर लिखा- मैं भारतीयों की गर्मजोशी की साइहना करती हूँ। मैंने कई नए दोस्त बनाए हैं। 1990 के दशक में भारतवंशी कमरा: डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने 60.40 अनुपात में समर्थन देते रहे, लेकिन 9/11 के हमले के बाद अमेरिका में अप्रवासी समुदाय के खेलाफहमले बढ़ गए। रिपब्लिकन

न खुद का इसाइ धर्म का प्रचार ने वाले और अप्रवासियों के प्रति उत रखने वाले समूहों से जोड़ दी। भारतीयों का रिपब्लिकन पार्टी ने अपराधज्ञाकाव कर्म होता गया। 1945 में तो 20: से कम भारतीयों ने रेलकन पार्टी का समर्थन किया। वी वजह यह रही कि रिपब्लिकन नेतृत्वार द्रम्प ने अपने प्रचार में असियों के खिलाफस्थल नीति ने की बात जोरशोर से उठाई। भी बड़े पैमाने पर द्रम्प को यैन निलना फिलाहाल संभव नहीं रहा है।

वयोंकि, आव्रजन पर की नीतियों ने उच्च शिक्षित भारतीय अमेरिकियों के हितों परोट पहुंचाई है। उन्होंने एच-बी की संख्या सीमित करने के प्रशासन के फैसले की बेचना की है। इसके अलावा, प्रशासन ने एच-बी वीसा पाने के जीवनसाथी के वर्कर परमिट द करने की इच्छा भी व्यक्त की गयी है। ऐसा भी हो सकता है कि भारतवंशी डोनाल्ड द्रम्प को

मादा त एक स अधिवे गतिविधि चुनाव ही वाल बाइडेन की स का स केवल उनकी क्रमशः नाईक होगा। चुनाव होती है अपार अवसर जिनमें तौर पर्याधार भाग्य उद्घव उम्मीद इन व प्रदर्शन

सब्धा का नजारए से देख। तक चले प्रारम्भिक घटनों, जो और अन्य प्रधारणीयों के बाद अब राष्ट्रपति पने अंतिम दौर में पहुंचने हैं। 29 सितम्बर से जो और डोनाल्ड ट्रम्प वादविवादों के फ़िक्क श्रृंखला में एक-दूसरे जा करेंगे। इसमें व्यवधान अवटूबर को आयेगा जब पराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला देवी हैरिस और ज्ञस का प्रत्यक्ष मुकाबला बहसे निर्णयदेह किसी भी नी सबसे बड़ी परिषट्टनाएँ इन्हें देखने वालों की संख्या जी है और वे ऐसे गिने-चुने का प्रतिनिधित्व करती हैं त्यारी एक-दूसरे का सीधे मुकाबला करते हैं। इन ने पूर्व में अनेक चुनावों के य किये हैं। टेलीविजन के बाद तो लगभग वे ही जीतते आये हैं जिन्होंने विवाद प्रतिष्पर्धाओं में बेहतर किया हो। अनेक तो

# सम्पादकाय

## लोकतंत्र बनाम तानाशाही

आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व चान ने त्यानमन स्क्रियर में भा  
लोकतान्त्रिक आवाज को बेरहमी से कुचला था। इसमें कोई संशय नहीं  
है कि पश्चिमी देशों द्वारा लोकतंत्र को अपनाये जाने से मानव विकास  
को भारी गति मिली है। लोकतंत्र में हर नागरिक को खुलापन मिलता  
है और वह अपनी सृजनात्मक शक्ति का उपयोग कर सकता है जैसे  
जेम्स वाट द्वारा स्टीम इंजन को बनाया जाना अथवा बिलगेट्स द्वारा  
विंडेस साप्ट वेयर को बनाया जाना। इसी क्रम में हम देखते हैं कि  
अमरीकी लोकतंत्र ने पिछली शताब्दी में एटमबम, जेट इंजन, इंटरनेट  
जैसे आविष्कार किये ज्योकि उसने अपने नागरिकों को लोकतान्त्रिक  
खुलापन उपलब्ध कराया। सच है कि रूस और चीन द्वारा भी तमाम  
आधुनिक उपकरण बनाये गये हैं लेकिन मूल रूप से नया सृजन तो  
लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही हुआ है। रूस और चीन ने  
मुख्यतरूप पश्चिमी देशों द्वारा किये गये आविष्कारों की नकल करने में  
सफलता मात्र हासिल की है। साथ-साथ यह भी देखा जाता है कि लम्बे  
समय तक लोकतान्त्रिक व्यवस्था तभी सफल होती है जब वह दूसरे  
देशों का शोषण करे। वर्तमान युग में लोकतंत्र की शुरुआत यूनान में  
आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। यूनान के लोगों ने लोहे का  
आविष्कार किया था। उन्होंने लोहे के अस्त्रों के बल पर अपने पड़ोसियों  
को लूटा और उस लूट से मिली समृद्धि के बल पर वे लोग लम्बी-  
लम्बी लोकतान्त्रिक चर्चाएं करने का आर्थिक बोझ बहन कर सके थे।  
उनके लिए लम्बे समय तक चर्चा में लगे रहना इसलिए संभव था  
क्योंकि उनके पास लूट की रकम उपलब्ध थी जिससे भोजन इत्यादि  
आसानी से मिल जाता था। लेकिन शीघ्र ही लूटने लायक पड़ोसी लोग  
नहीं बचे, लूट की रकम उपलब्ध नहीं हुई और लम्बी लोकतान्त्रिक  
चर्चाएं स्वतंत्र ध्वस्त हो गईं। यूनान का लोकतंत्र समाप्त हो गया। इसके  
बाद रोम में लोकतंत्र का उदय हुआ। उन लोगों ने घुड़सवार को लोहे  
के कवच उपलब्ध कराए और इस अस्त्र के बल पर उन्होंने बड़े क्षेत्र  
में दूसरों को लूटा। पुनः लूट से लाई रकम से उन लोगों ने अपने देश  
में लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू की। जैसे ही लूटने के लिए दूसरे देश  
उपलब्ध नहीं रहे, रोम का लोकतंत्र टुकड़े-टुकड़े हो गया। लोकतंत्र का  
उदय पुनरु मध्य युग में हुआ। यह वही समय है जब इंग्लैण्ड ने भारत  
जैसे तमाम देशों को अपना उपनिवेश बना लिया था। इंग्लैण्ड में बना  
महांगा माल उपनिवेशों को बेच कर, एवं उपनिवेशों के घेरे उद्योगों को

के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है औ जीडीपी में यह गिरावट कृषि को छोड़ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में दिखायी दे रही है जबसे जीडीपी के आंकड़े प्रकाशित होना शुरू हुए, तब से यह पहली ऐसी घटना है, जब किसी एक तिमाही में जीडीपी में इतनी बड़ी गिरावट आयी है, हालांकि, यह गिरावट बड़ी है, लेकिन अप्रत्याशित कर्तव्य नहीं है ऐसभी जानकार मान रहे थे कि इस तिमाही में जब पूरा देश लॉकडाउन में रहा, उत्पादन केंद्र समेत तमाम सेवाएं बंद थीं अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के अलावा सामान्यतरू किसी अन्य का इलाज नहीं हो रहा था औ अधिकांश मजदूर वापस अपने घर चले गये थे, ऐसे में जीडीपी में गिरावट संभावित ही थी जब किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी वृद्धि प्रभावित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी उस देश की सरकार की आर्थिक नीतियों और कार्य निष्पादन पर आती है औ लेकिन जीडीपी में यह गिरावट सरकार की नीतियों की खामियों के कारण नहीं, बल्कि ईश्वरीय आपदा के कारण है जो कोरोना संक्रमण के दौरान आर्थिक गतिविधियों में जहां 23.9 प्रतिशत की गिरावट ही, वहीं इंलैंड में यह गिरावट 20.4, प्रांस में 13.8, इटली में 12.4, कनाडा में 12, जर्मनी में 10 और अमेरिका में 32 प्रतिशत रही, प्रश्न है कि अमेरिका को छोड़, अन्य देशों की तुलना में भारत की जीडीपी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आयी? क्योंकि भारत लॉकडाउन सबसे पहले लगाया, जबकि शेष देशों ने लगाने में देरी की अर्थव्यवस्था बाधित न हो, इस कारण अमेरिका, यूरोप के देशों, ब्राजील आदि लॉकडाउन टालते रहे, देखते हुए कि अन्य देशों तुलना में देश में स्वास्थ्य सुविधा कम है और संक्रमण फैलने स्थिति में हम उससे निपटना पायेंगे, भारत सरकार लॉकडाउन जल्दी से लागू किया, दुनिया के विकसित देश गुमान में थे कि उनके पास उस स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और महामारी से निपटने में वे पूरी तरह सहायता हैं, उन्होंने लॉकडाउन में देरी बढ़ावा परिणाम हमारे सामने है, अमेरिका की जनसंख्या मात्र 33 करोड़, भारत की जनसंख्या से 10 गुना चौथाई से भी कम, वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या भारत में 39.3 लाख की तुलना में 69

लाख लाग कारोना से संक्रमित हो चुके हैं, भारत में कोरोना संक्रमण से होनेवाली मृत्यु दर 1.75 प्रतिशत है, अमेरिका में यह दर 3.1 प्रतिशत, ब्राजील में 3.2 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका में 2.1 प्रतिशत है, इटली में यह दर 13.7 प्रतिशत रही, अमेरिका तो अपनी अर्थव्यवस्था भी नहीं बचा पाया, भारत जानता था कि देश में टेस्टिंग की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे में सरकार के पास दो विकल्प थे, अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जीवन को सामान्य रूप से चलाये रखा जाये, या जीवन बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाये, इस बीच अस्पताल, दवाइयां, वैटिलेटर, पीपीइ किट्स और टेस्टिंग सुविधाओं को बेहतर किया जाये, भारत सरकार ने दूसरा विकल्प चुना, शेष दुनिया ने भी दूसरा विकल्प चुना, लेकिन देरी से, इसलिए इन देशों में पिछली तिमाही में जीडीपी में गिरावट तो आयी, लेकिन यह गिरावट देरी से आना शुरू हुई, देश और दुनिया की जीडीपी में गिरावट अल्पकालिक ही है, क्योंकि संक्रमण समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने वाली है, मांग में आयी वर्तमान कमी की भरपायी भी आनेवाले

जाता है, कारों की बढ़ती मांग से इस बात का आभास होना शुरू हो चुका है, भारत ने इस महामारी से आत्मनिर्भरता की एक बड़ी सीख ली है, पिछले दो दशकों से हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही थी, इस कारण हमारे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था, वर्ष 2012 से 2015 तक हमारे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वृद्धि लगभग शून्य तक पहुंच गयी थी, पिछले कुछ समय से उसमें थोड़ा-बहुत सुधार दिखायी दे रहा

नर नहीं पड़ा था, महामारी के बढ़ने के साथ आवश्यक पीपीइ किट, केंटिलेटर, टेस्टिंग किट और चिकित्सा उपकरणों का देश अत्यादन बढ़ाकर, अपनी और दूसरी देशों की आवश्यकताओं पूर्ति करने से देश में त्वचिक्षास का वातावरण बना सकार ने संकल्प लिया है कि त्वचनभर्ता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दवा उद्योगों के एवं कच्चा माल (एपीआई), कट्टौनिक्स, केमिकल्स, बढ़ाया जायेगा, उसके लिए सरकारी सहायता समेत सभी जरूरी उपाय किये जायेंगे, शेष दुनिया की कई कंपनियां जो चीन में कार्यरत थीं, उनमें से कई भारत में आ रही हैं यानी, भविष्य में औद्योगिक और प्रौद्योगिकी विकास के नये अवसर मिलने वाले हैं; जीडीपी में वर्तमान संकुचन आया है, लेकिन भविष्य उज्जवल है, इसके लिए सरकार, उद्योग और जनता सभी को प्रयास करने होंगे।

# सत्ताभागिया का कमयागिया संबद्ध

आर दाशानक बात कहा है कि नौकरशाही किसी भी उपलब्ध की मृत्यु है. फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को विश्वास है कि अक्षम नौकरशाही को उपयोगी बनाया सकता है. परिवर्तनकारी पहल करते हुए उन्होंने बाबूशाही में बदलाव शुरू किया है. हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल अभियान आइजीओटी-कर्मयोगी की शुरुआत की है. सरकार के मुताबिक, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भविष्य के भारतीय प्रशासनिक सेवकों को तैयार करना है, जिसके लिए उन्हें रचनात्मक, सुजनात्मक, कल्पनाशील, नवोन्मेषी, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी तौर पर निपुण बनाया जायेगा. विशिष्ट भूमिका-दक्षताओं से युक्त, सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ प्रभावी सेवाओं को सुनिश्चित करेंगे. इसे 'प्रशासनिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम क्षमता निर्माण (एनपीसीएससीबी)' के तौर पर

‘आपूर्त अथशास्त्र’ से सचालत हो रही हैं। वर्ष 1991 से वामदलों को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों ने अत्यधिक क्षमता निर्माण को आंख मूंकर समर्थन दिया है। चार दशक बाद, मांग में आयी गिरावट की वजह से अर्थव्यवस्था संकट में है। मौजूदा व्यवस्था में क्षमता बढ़ोतरी पर अत्यधिक जोर देकर, एनडीए सरकार कुटिल सिविल सेवा के ट्रैप में फँस गयी है। नये प्रेमवर्क में जवाबदेही और समयबद्ध डिलिवरी सिस्टम की उम्मीद शायद ही की जा सकती है। दुर्भाग्य से, भारतीय अर्थव्यवस्था और इसका प्रभावी प्रशासन दो करोड़ पब्लिक अधिकारियों की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता पर निर्भर है, जिन्हें लगभग 15,000 आइएस अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यद्यपि बाबू लोग प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्य लोकतांत्रिक तरीके से चुने गये प्रतिनिधियों को रिपोर्ट करते हैं। निर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा पास नीतियों और योजनाओं को

जवाबदह हात ह. यहा तक कि खराब प्रदर्शन के कारण अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मतदाताओं द्वारा बेदखल कर दिये जाते हैं, तो भी डीएम की प्रोत्रति हो जाती है. नौकरशाही को सफलता के लिए नहीं, बल्कि स्पष्ट विफलता के लिए पुरस्कृत किया जाता है. चूंकि, उन्हें जानकारियां सबसे पहले मिलती हैं, रुतबा बचाये रखने के लिए वे अक्सर इसका इस्तेमाल राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ करते हैं. भारत पहले से ही लालची बाबूगिरी के बोझ से दबा है. एक चालाक सिविल सेवक हमेशा ऐसे किसी बदलाव या रचनात्मक परिवर्तन का विरोध करता है, जो उसकी ताकत को सीमित करता हो और लापरवाही के लिए कार्रवाई तय करता हो. प्रधानमंत्री ने सही कहा था कि उनकी सरकार, न्यूनतम सरकार के साथ अधिकतम शासन को सुनिश्चित करेगी, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत की व्यवस्था बाह्य दिखावा है. गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वे सतर्क थे कि उनकी किसी भी अधिकारी को बेकामी के लिए नौकरशाही के बजाय वृद्धि पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गयी है. आजादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण भारत में संपर्क मार्ग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, व्यवस्थित विद्यालय और स्वच्छ जलापूर्ति का अभाव है, तो इसके लिए जवाबदेह कौन है? इसमें गलती केवल नेताओं की नहीं है. राज्यों और केंद्र के बजटों से पर्याप्त धन का आवंटन किया गया है. लेकिन, इस राशि के सही इस्तेमाल के लिए नौकरशाहों की कोई जवाबदेही नहीं है. राजीव गांधी ने कहा था कि विकास कार्यों के लिए आवंटित एक रूपये में से केवल 15 पैसा ही लोगों तक पहुंचता है. जब सीएजी परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितता और खरीद में हेराफेरी बताते हैं, तो क्यों निवाचित प्रतिनिधि ही केवल न्यायिक जांच और दंड का समाना करते हैं? वहीं फ़इल बढ़ानेवाले छूट जाते हैं, जबकि वे फ़इल को एक टेबल से दूसरे टेबल बढ़ाते हुए उनकी बात से बाहर नहीं जाती है. जब तक नुकसानदेह अप्सरशाही के चरित्र को बदला नहीं जायेगा, तब तक कोई भी मिशन, यहां तक कि सीबड़े विजन के साथ भी, बेहतर शासन नहीं लाया जा सकता है.



